माननिए मुख्य न्यायमूर्ति एस.जे.वजीफदार & माननिए न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल

चंडीगढ़ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और अन्य-याचिकाकर्ता बनाम

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ अपने सचिव इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ और अन्य के माध्यम से - प्रतिवादी

2017 की सीडब्ल्यूपी संख्या 9895

मई 23, 2017

भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 और 227 – ई-निविदाओं के लिए आमंत्रण – बोलीदाताओं की योग्यता – याचिकाकर्ता गैर-सीपीडब्ल्यूडी ठेकेदार थे अर्थात वे सीपीडब्ल्यूडी के साथ पंजीकृत नहीं थे – हालांकि वे केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के साथ पंजीकृत थे – माना जाता है, यदि योग्यता और पात्रता के लिए आवश्यक है कि बोलीदाता सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार होने चाहिए, तो न्यायालय बदल नहीं सकता है, इस तरह के खंड में संशोधन या संशोधन - निविदाएं आमंत्रित करने वाली पार्टी अपने स्वयं के पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए पात्र है - उन्हें किसी अन्य संगठन या उद्यम के साथ मान्यता स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया की इस तर्क में दम नहीं है क्योंकि दूसरा उपअनुच्छेद इस वाक्यांश से शुरू होता है "लेकिन ऐसी बोलियों के लिए, सीपीडब्ल्यूडी के श्रेणी-I ठेकेदार ..." (महत्व दिया)। याचिकाकर्ता क्लास-1 ठेकेदारों के रूप में अपनी स्थिति का दावा करते हैं; हालांकि, वे स्वीकार करते हैं कि वे सीपीडब्ल्यूडी के साथ पंजीकृत नहीं हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता नंबर 1 और उसके सदस्यों को गैर-सीपीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपपैराग्राफ में उल्लिखित छूट पूरी तरह से सीपीडब्ल्यूडी के श्रेणी-I ठेकेदारों पर लागू होती है, जो सीपीडब्ल्यूडी के साथ पंजीकृत लोगों को दर्शाती है।

(पैरा 5)

यह भी अभिनिर्धारित किया की यह तर्क दिया गया कि पहले याचिकाकर्ता से जुड़े व्यक्ति आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के साथ पंजीकृत हैं। यह देखते हुए कि केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा निविदाएं जारी की गई हैं, यह सुझाव दिया गया था कि सीपीडब्ल्यूडी -6 के खंड 1.2.3 में शब्द, जिसमें "सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार" का उल्लेख है, को राज्य "केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के ठेकेदार" में संशोधित किया जाना चाहिए।

(पैरा 6)

यह भी अभिनिर्धारित किया की हमें सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के ठेकेदार रखकर खंड को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। पात्रता शर्तों को परिभाषित करने के लिए निविदा जारी करने वाली पार्टी की जिम्मेदारी है, जिसमें कोई छूट, संशोधन या छूट शामिल है। निविदाएं आमंत्रित करने वाली पार्टी पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए अधिकृत है, जिसमें किसी विशिष्ट संगठन या उद्यम के साथ पंजीकरण की आवश्यकता शामिल हो सकती है। यह माना जाता है कि निविदाएं जारी करने वाली पार्टी ने निर्दिष्ट संगठन या उद्यम के साथ पंजीकरण के लिए आवश्यक योग्यताओं का आकलन किया है और उन्हें उस कार्य के सफल

निष्पादन के लिए पर्याप्त माना है जिसके लिए निविदाएं मांगी जा रही हैं। नतीजतन, पार्टी को किसी अन्य संगठन या उद्यम के साथ पंजीकरण स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, खासकर अगर यह पंजीकरण आवश्यकताओं से परिचित नहीं है या उन्हें इच्छित कार्य के लिए उपयुक्त नहीं मानता है। अदालतें निविदाएं जारी करने वाली पार्टी को पात्रता मानदंडों को पूरा करने के रूप में किसी विशिष्ट संगठन या उद्यम के साथ पंजीकरण स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज चावला।

दीपाली पुरी, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के लिए।

मुख्य न्यायमूर्ति एस.जे. वजीफदार, (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की एक रिट की मांग की है जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे उन्हें कार्य अनुभव प्रमाण पत्र और हलफनामा प्रस्तुत किए बिना ई-निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस के संबंध में अपनी बोली प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

(2) ई-निविदाएं आमंत्रित करने वाली मुख्य सूचना में निम्नलिखित खंड शामिल हैं:-

> “4. बोलीदाता के लिए योग्यता मानदंड:- इच्छुक निविदाकर्ता को पिछले 7 (सात) वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए, जो महीने से पहले महीने के अंतिम दिन को समाप्त होता है, जिसमें बोली आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं (यानी पात्रता अवधि) निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए: -
>
> "तीन तुलनीय तैयार परियोजनाएं," प्रत्येक अनुमानित निविदा लागत का न्यूनतम 40% मूल्य है।
>
> "दो अनुरूप पूर्ण परियोजनाएं," प्रत्येक का मूल्य अनुमानित निविदा लागत का न्यूनतम 60% है।
>
> "एक तुलनीय तैयार परियोजना," निविदा में निर्दिष्ट अनुमानित लागत के 80% से कम नहीं है।
>
> 4.5 इच्छुक बोलीदाता को पात्रता मानदंडों को पूरा करने के समर्थन में विधिवत स्व-सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना होगा, जैसा कि ऊपर कहा गया है अर्थात कार्य आदेश (ओं), पूर्ण कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र और वित्तीय कारोबार आदि”

(3) अंत में ई-निविदाएं आमंत्रित करने वाली सूचना में कहा गया है: "एनआईटी दस्तावेज़ सीरियल नंबर दस्तावेज़ का नाम विवरण 1एनआइटी_1.पीडीएफ निविदा दस्तावेज”

> याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि यह प्रविष्टि "चंडीगढ़ बिजली विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन" शीर्षक से एक दस्तावेज पेश करती है। इस दस्तावेज़ के भीतर, सीरियल नंबर 3 को "ई-टेंडरिंग के लिए सीपीडब्ल्यूडी -6" के रूप में नामित किया गया है। परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि इस दस्तावेज़ में

"ई-निविदा के लिए सीपीडब्ल्यूडी-6" में उल्लिखित नियम और शर्तें शामिल हैं। याचिकाकर्ता इसके खंड 1.2.3 पर भरोसा करते हैं, जहां तक यह प्रासंगिक है, निम्नानुसार पढ़ता है: -

"सीपीडब्ल्यूडी-6 ई-टेंडरिंग के लिए

1.2.3 जब उपर्युक्त खंड 121 के प्रावधानों के अनुसार गैर-सीपीडब्ल्यूडी ठेकेदारों और सीपीडब्ल्यूडी श्रेणी-II ठेकेदारों से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, तो गैर-सीपीडब्ल्यूडी ठेकेदारों और सीपीडब्ल्यूडी श्रेणी-II ठेकेदारों के लिए खंड 1.2.2 के प्रावधानों के अनुसार कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (ओं) और शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

लेकिन ऐसी बोलियों के लिए केलोनिवि के श्रेणी-I ठेकेदार कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र और शपथ-पत्र प्रस्तुत किए बिना बोलियां प्रस्तुत करने के पात्र हैं। इसलिए, सीपीडब्ल्यूडी वर्ग-I ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र और शपथ पत्र के लिए दो अलग-अलग पत्र अपलोड करेंगे कि इन दस्तावेजों को उनके द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा सिस्टम अनिवार्य फील्ड को क्लियर नहीं करेगा।

(4) याचिकाकर्ता ऊपर उद्धृत सीपीडब्ल्यूडी -6 के खंड 1.2.3 के दूसरे उप-पैरा पर भरोसा करते हैं कि वे कार्य अनुभव प्रमाण पत्र और हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क नहीं है कि वे पहले उद्धृत निविदा नोटिस के खंड 4 में निर्धारित कार्य अनुभव के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। वे केवल यह तर्क देते हैं कि वे कार्य अनुभव प्रमाण पत्र और हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

(5) इस तर्क में दम नहीं है क्योंकि दूसरा उपअनुच्छेद इस वाक्यांश से शुरू होता है "लेकिन ऐसी बोलियों के लिए, सीपीडब्ल्यूडी के श्रेणी-I ठेकेदार ..." (महत्व दिया)। याचिकाकर्ता क्लास-1 ठेकेदारों के रूप में अपनी स्थिति का दावा करते हैं; हालांकि, वे स्वीकार करते हैं कि वे सीपीडब्ल्यूडी के साथ पंजीकृत नहीं हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता नंबर 1 और उसके सदस्यों को गैर-सीपीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपपैराग्राफ में उल्लिखित छूट पूरी तरह से सीपीडब्ल्यूडी के श्रेणी-I ठेकेदारों पर लागू होती है, जो सीपीडब्ल्यूडी के साथ पंजीकृत लोगों को दर्शाती है।

(6) इस स्थिति के जवाब में, यह तर्क दिया गया कि पहले याचिकाकर्ता से जुड़े व्यक्ति आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के साथ पंजीकृत हैं। यह देखते हुए कि केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा निविदाएं जारी की गई हैं, यह सुझाव दिया गया था कि सीपीडब्ल्यूडी -6 के खंड 1.2.3 में शब्द, जिसमें "सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदार" का उल्लेख है, को राज्य "केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के ठेकेदार" में संशोधित किया जाना चाहिए।

(7) हमें सीपीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के ठेकेदार रखकर खंड को संशोधित करने का अधिकार नहीं है। पात्रता शर्तों को परिभाषित करने के लिए निविदा जारी करने वाली पार्टी की जिम्मेदारी है, जिसमें कोई छूट, संशोधन या छूट शामिल है। निविदाएं आमंत्रित करने वाली पार्टी पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए अधिकृत है, जिसमें किसी विशिष्ट संगठन या उद्यम के साथ पंजीकरण की आवश्यकता शामिल हो सकती है। यह माना जाता है कि निविदाएं जारी करने वाली पार्टी ने निर्दिष्ट संगठन या उद्यम के साथ पंजीकरण के लिए आवश्यक योग्यताओं का आकलन किया है और उन्हें उस कार्य के सफल निष्पादन के लिए पर्याप्त माना है जिसके

लिए निविदाएं मांगी जा रही हैं। नतीजतन, पार्टी को किसी अन्य संगठन या उद्यम के साथ पंजीकरण स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, खासकर अगर यह पंजीकरण आवश्यकताओं से परिचित नहीं है या उन्हें इच्छित कार्य के लिए उपयुक्त नहीं मानता है। अदालतें निविदाएं जारी करने वाली पार्टी को पात्रता मानदंडों को पूरा करने के रूप में किसी विशिष्ट संगठन या उद्यम के साथ पंजीकरण स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं।

(8) इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार , हरियाणा